विचार बिन्दु

पुरुष का नारी के समान कोई बंधू नहीं। –महाभारत

''तेरा सनातन - मेरा सनातन, हमारे वाला भगवान - उन वाला भगवान'' - इस बहस पर एक तथ्यात्मक टिप्पणी

आजकल 'सनातन' शब्द टीवी डिबेट, सोशल मीडिया और राजनेताओं, धर्माचार्यों, कथावाचकों के भाषणों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द बन गया है। हर कोई अपने हिसाब से इसकी परिभाषा देता है। इसी से 'तेरा सनातन' और 'मेरा सनातन' वाली स्थिति बन गई है। अब तो बात यहाँ तक बिगड गई है कि भगवानों को भी 'हमारे वाले' और 'उन वाले' कहा जा रहा है।

सनातन का मूल अर्थ क्या है?

शब्दकोश और शास्त्रों के अनुसार सनातन का अर्थ है - जो हमेशा से है, जिसका न आदि है न अंत। मनुष्यों के संदर्भ में यह शाश्वत जीवन जीने की पद्धति है। यह किसी एक व्यक्ति, पंथ या किताब पर आधारित नहीं है। गीता में कृष्ण ने कहा - - मैं सनातन हूँ। सनातन एक 'व्यक्ति' नहीं, एक 'प्रवाह' है।

ऐतिहासिक तथ्य यह है कि सनातन की शक्ति एकरूपता में नहीं, विविधता में एकता में है। कोई मूर्ति पूजता है, कोई निराकार को, कोई प्रकृति को ही ईश्वर मानता है। छह आस्तिक दर्शन - सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त - सबकी चर्चा अलग है। शंकराचार्य, रामानुज, माधव, कबीर, नानक - सबकी व्याख्या अलग थी, पर सब सनातन के अंदर माने गए।

शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त, सौर - इन पंथों ने एक-दूसरे को कभी 'विधर्मी' नहीं कहा। खानपान में कोई मांसाहारी, कोई शाकाहारी। एक जैसा सनातन इतिहास में कभी था ही नहीं।

'तेरा-मेरा' क्यों हो रहा है? इसके दो मुख्य कारण हैं - राजनीति और बाजार।

राजनेताओं ने सनातन को वोट बैंक की पहचान बना लिया है। ''हम सच्चे सनातनी'' कहकर दूसरे को नकली, सनातन विरोधी घोषित करना आसान हो जाता है।

इसका दूसरा उपयोग बाबाओं, कथा वाचकों के प्रवचनों में होता है। हर बाबा को अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कहना पडता है कि ''मेरी वाली व्याख्या ही असली है।'' विभाजन वाली बात सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल होती है। 'सब धर्म एक हैं' वाली बात को कोई शेयर नहीं करता।

सनातन की असली परंपरा क्या है?

सनातन में धर्म को समझने के लिए बहस की परंपरा ही सनातन है। उपनिषद से लेकर शंकराचार्य तक, 'वाद-विवाद' को ज्ञान का रास्ता माना गया। विरोध को अपराध नहीं माना गया।

ऋग्वेद कहता है - सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग-अलग तरह से बताते हैं।

सनातन धर्म के 10 लक्षण गिनाए जाते हैं यथा -- धैर्य(धृति), क्षमा, दम(मन पर नियंत्रण), अस्तेय(चोरी न करना), शौच अर्थात पवित्रता, इंद्रिय निठाह, धी(सद्बुद्धि), सही ज्ञान, सत्य और अक्रोध। संसार के सभी प्रमुख धर्मों में यही नियम धर्माचरण के हैं। किसी के कपडे, टोपी या नारे से सनातन की पहचान कभी नहीं रही।

जब तक सनातन को वोट और व्यापार/बाजार/मीडिया द्वारा का हथियार बनाया जाएगा, ''तेरा सनातन-मेरा सनातन'' चलता रहेगा। जब इसे ''जीवन जीने की कला'' माना जाएगा, तब झगड़ा खत्म होगा।

समस्या सनातन में नहीं, ''एक्सक्लूसिविटी'' में है - सनातन को मेरे-तेरे में बांटने में है। ''मेरा सनातन ही असली है, बाकी सब अधर्मी हैं'' कहना स्वयं सनातन के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।

कट्टरता की काट के 5 सिद्धांत

शास्त्रों में बार-बार जिन 5 बातों पर जोर है, वही कट्टरता की काट हैं:-

1. एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति (ऋग्वेद 1.164.46)- बहुत से रास्ते हैं, सिर्फ मेरा रास्ता सही कहना गलत है।

2. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया- इसमें हम और वो नहीं, सबकी मंगल कामना है।

3. वसुधैव कुटुम्बकम् (महोपनिषद 6.72) - पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इसीलिए भारत में पारसी, यहूदी, ईसाई सबको शरण मिली।

4. अहिंसा परमो धर्मः (महाभारत) - पहले शब्दों की हिंसा, फिर बहिष्कार, फिर शारीरिक हिंसा। गीता के 16वें अध्याय में क्रोध, निष्ठुरता, अज्ञान को आसुरी गुण कहा गया है।

5. जिज्ञासा और संवाद- प्रश्न पूछो, तर्क करो, बहस करो। कट्टरता सवाल बंद कर देती है, सनातन सवाल से शुरू होता है।

जब हम इन 5 सिद्धांतों को भूलकर सनातन को सिर्फ बाहरी पहचान - टोपी, तिलक, नारा, झंडा - बना देते हैं, तब झगड़ा शुरू होता है।

राजनीति में सनातन का इस्तेमाल ------ 1980 के दशक से राजनीति में ''सनातन'' शब्द का इस्तेमाल बढ़ा है। 2014 के बाद चुनावी भाषणों में ''सनातन, हिंदू आस्था, मंदिर'' जैसे शब्दों का उपयोग बहुत अधिक बढ़ा है। इनका उपयोग सहज भाव से नहीं, विभाजनकारी भाव से किया जाता है - जैसे हम सनातन को बचाने वाले हैं, वो सनातन को गाली देते हैं।

इससे मतदाताओं को जाति, क्षेत्र से ऊपर एक 'सनातन' पहचान में लाने का प्रयास होता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है। सीएए, मंदिर निर्माण, गो-रक्षा कानून, एंटी-कन्वर्जन कानून आदि को सनातन मूल्यों की रक्षा बताकर विरोध करने वालों को 'सनातन विरोधी' घोषित करना आसान हो जाता है।

आज कट्टरता के 3 रूप

पहला - सिर्फ मूर्ति पूजा ही सनातन है, जबकि स्मार्त, आर्य समाज, निरंकारी सभी खुद को सनातनी कहते हैं।

दूसरा - दूसरों को दुश्मन मानना - ''अगर तुम ये नहीं मानते तो तुम सनातन विरोधी हो'', जबकि परंपरा में नास्तिक चार्वाक को भी बहस में जगह मिली।

तीसरा - हिंसा को जायज ठहराना - सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, बहिष्कार, मारपीट, जो शास्त्र विरुद्ध है।

सनातन के नाम पर कुछ बाबाओं की प्रमुख आवाजें:-

आज बाबा रामदेव, जगदुरु रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषद - सबकी भाषा में एक समानता है - भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, धर्मांतरण रोको, जनसंख्या संतुलन के लिए हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए।

दूसरा पक्ष कहता है - भारत संविधान से 'पंथनिरपेक्ष' है, हिंदू राष्ट्र की मांग संविधान के खिलाफ है। जनसंख्या वाला बयान एक धर्म को टार्गेट करता है और महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण की बात कहता है।

एक पक्ष सनातन को ''पॉलिटिकल आइडेंटिटी'' बनाता है, दूसरा उसके 'खतरे' बताता है। जनता भ्रमित होकर असली मुद्दों से हटकर आपसी झगड़ों में फंस जाती है।

निष्कर्ष:- सनातन में कट्टरता की परंपरा कम है क्योंकि इसमें किसी एक मुखिया का फतवा नहीं है। शंकराचार्य ने बौद्धों, जैनों से शास्त्रार्थ किया। हारने वाला अपना मत बदल लेता था, मारा नहीं जाता था।

चूंकि 80-90 प्रतिशत लोग गीता-उपनिषद नहीं पढते, केवल व्हाट्सएप के 30 सेकंड के वीडियो से ज्ञान लेते हैं, इसलिए कट्टरता फैलती है।

जब तक सनातन को वोट और व्यापार/बाजार/मीडिया द्वारा का हथियार बनाया जाएगा, ''तेरा सनातन-मेरा सनातन'' चलता रहेगा। जब इसे ''जीवन जीने की कला'' माना जाएगा, तब झगड़ा खत्म होगा।

-अतिथि सम्पादक,
महावीर सिंह, पूर्व आइ ए एस

राशिफल शनिवार 14 नवम्बर, 2026



पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत-2083, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 8:14 तक, शूल योग रविवार प्रात: 6:22 तक, बव करण दिन 10:03 तक, चन्द्रमा रात्रि 3:11 से मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति- सूर्य-तुला, चन्द्रमा-धनु, मंगल-सिंह, बुध-तुला, गुरू-सिंह, शुक्र-कन्या, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग रात्रि 8:14 से आरम्भ होगा। शुक्र मार्गी प्रात: 5:55 पर होगा। आज सौभाग्य पंचमी व्रत, पांडव और लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी है। आज डाला छठ पर्व का दूसरा दिन है।

श्रेष्ठ चौघड़िया- शुभ 8:10 से 9:30 तक, चर 12:11 से 1:31 तक, लाभ-अमृत 1:31 से 4:12 तक।

राहुकाल- 9:00 से 10:30 तक, सूर्योदय 6:50, सूर्यास्त 5:32



मेष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक-मांगलिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है।



सिंह

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज रचनात्मक कार्यों में समय व्यतीत होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी।



धनु

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। आज परिवार में शुभ संदेश प्राप्त हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृष

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।



कन्या

घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मकर

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।



मिथुन

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।



तुला

आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। आज खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कुंभ

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



कर्क

व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी।



वृश्चिक

घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मीन

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कारणों से मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की ऐतिहासिक उपलब्धि



नंदिनी भार्गव



मोहन लाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व एवं राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों के परिणामस्वरूप राजस्थान अक्षय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। प्रदेश में अब तक 51.6 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता तथा 45 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना तथा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का उपयोग कर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा किसानों, युवाओं और निवेशकों के लिए विकास एवं रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं।

राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां, विशाल भू-भाग और वर्षभर उपलब्ध रहने वाली प्रचुर सूर्य की रोशनी इसे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनाती हैं। राज्य सरकार इन संभावनाओं को साकार करने के लिए बड़े सौर ऊर्जा पार्क, रूफटॉप सोलर, पवन ऊर्जा, बायोमास तथा ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लगभग 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। इसके साथ ही भारत सरकार के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म रहित ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के तीव्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार किया गया है। मेगा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राइट टू यूज नीति जारी की गई है। वहीं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यिमयों एवं निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन पहलों से प्रदेश में बड़े निवेश आकर्षित होने के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विस्तार हो रहा है। राज्य में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। सौर ऊर्जा के अतिरिक्त उत्पादन का प्रभावी उपयोग करने तथा बिजली की अधिकतम मांग के समय ग्रिड प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विकास की कार्ययोजना भी तैयार की गई है।

सौर ऊर्जा उत्पादन में लगातार हो रही वृद्धि का सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के कृषि क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है। राज्य के 28 जिलों के किसानों को दिन के समय कृषि कार्यों एवं सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए सुविधाजनक समय पर बिजली मिलेगी तथा कृषि कार्यों में निर्भरता और अनिश्चितता कम होगी।

राज्य सरकार का प्रयास है कि ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि का लाभ केवल औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिले। इसी सोच के अनुरूप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ने और किसानों को ऊर्जा उत्पादन में भागीदार बनाने की दिशा में पीएम-कुसुम योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजस्थान की धरती पर सूर्य की प्रचुर रोशनी अब किसानों के लिए चुनौती के बजाय आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बन रही है।खेतों में स्थापित हो रहे सोलर पंप और कृषि भूमि पर विकसित किए जा रहे सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश की खेती को नई दिशा दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) का उद्देश्य किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाना, डीजल पर निर्भरता कम करना तथा कृषि क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। पीएम-कुसुम योजना को तीन प्रमुख घटकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक घटक के माध्यम से किसानों को उनकी आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप सौर ऊर्जा से जुड़ने के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

घटक- : कृषि भूमि से बिजली उत्पादन और नियमित आय का अवसर

योजना के घटक- के अंतर्गत किसान अपनी बंजर अथवा अनुपयोगी कृषि भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए किसान स्वयं निवेश कर सकता है अथवा किसी परियोजना विकासकर्ता के साथ साझेदारी कर सकता है। किसान अपनी भूमि विकासकर्ता को पट्टे पर देकर भी नियमित आय अर्जित कर सकता है। संयंत्र से उत्पादित बिजली संबंधित विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से निर्धारित दर पर खरीदी जाती है।

राजस्थान में इस घटक के अंतर्गत परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि निकटतम विद्युत सब-स्टेशन से पांच किलोमीटर के दायरे में होनी आवश्यक है। खेती योग्य भूमि पर ऊंचे ढांचे पर सौर पैनल स्थापित कर उनके नीचे खेती जारी रखने की व्यवस्था भी की जा सकती है। इससे एक ही भूमि का उपयोग कृषि और ऊर्जा उत्पादन दोनों कार्यों के लिए संभव हो पाता है।

घटक- : डीजल पंपों से मुक्ति और सौर ऊर्जा से सिंचाई

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक किसान सिंचाई के लिए डीजल पंपों पर निर्भर रहे हैं। डीजल की बढ़ती लागत और उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए योजना का घटक- किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके तहत ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में स्टैंडअलोन सोलर कृषि पंप स्थापित किए जाते हैं। सामान्य योजना प्रावधानों के अनुसार 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

घटक- : कृषि बिजली कनेक्शन का सौरकरण और अतिरिक्त बिजली से आय

योजना का घटक- पहले से ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर केंद्रित है। इसमें व्यक्तिगत पंप सौरकरण और फीडर स्तर सौरकरण की व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत पंप सौरकरण के तहत किसान अपनी सिंचाई की आवश्यकता पूरी करने के बाद अतिरिक्त उत्पादित बिजली निर्धारित व्यवस्था के अनुसार डिस्कॉम को बेच सकता है। वहीं, फीडर स्तर सौरकरण के माध्यम से कृषि क्षेत्र को दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाने की व्यवस्था को मजबूती मिलती है। इससे कृषि क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने में मदद मिलती है।

पीएम-कुसुम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। राजस्थान में पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का उल्लेखनीय उदाहरण जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील के भालोजी गांव में देखने को मिला है। यहां 3.5 एकड़ कृषि भूमि पर एक मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इस परियोजना की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 17 लाख यूनिट बताई गई है। भालोजी गांव की यह परियोजना इस बात का उदाहरण है कि किसान अपनी अनुपयोगी अथवा कम उपयोग में आने वाली भूमि का बेहतर इस्तेमाल कर उसे आय का अतिरिक्त स्त्रोत बना सकते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाएं विकसित होने के साथ ठाामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

राज्य में सामान्य किसानों के लिए न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व की सीमा अधिसूचित की गई है, जबकि अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए अधिसूचित जनजाति के किसानों के लिए यह सीमा 0.2 हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सोलर पंप स्थापित करने की सुविधा केवल कुएं और ट्यूबवेल तक सीमित नहीं रखी गई है। किसान निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने खेत में बने फार्म पॉन्ड, वॉटर टैंक और डिग्गी के लिए भी सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं।

सौर पंपों की स्थापना में आने वाली शुरुआती लागत को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अक्षय ऊर्जा का विस्तार केवल बिजली उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई से डीजल पंपों पर निर्भरता कम होती है, जिससे जीवाश्म ईंधन की खपत और उससे होने वाले प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलती है।

इसी प्रकार कृषि भूमि पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। कृषि फीडरों के सौरकरण से किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। वहीं, ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग आवश्यकता के समय किया जा सकता है। इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और ग्रिड प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार का मानना है कि योजनाओं की सफलता का वास्तविक आकलन केवल स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनके समयबद्ध क्रियान्वयन, नियमित संचालन और लाभार्थियों तक वास्तविक लाभ पहुंचने से होता है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप सोलर पंपों के रखरखाव, तकनीकी सहायता, अतिरिक्त बिजली की खरीद तथा भुगतान प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना आवश्यक है। किसानों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अनुदान से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध करवाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भारत सरकार ने पीएम-कुसुम योजना की कार्यान्वयन अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई है। इससे स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने और योजना का लाभ अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के समन्वय से प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को नई गति मिले तथा किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। 51.6 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता और 45 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना प्रदेश की इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वर्ष 2030 तक लगभग 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य राज्य को देश के ऊर्जा परिदृश्य में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहा है।

राजस्थान की धरती ने सदैव विपरीत परिस्थितियों में भी अन्न उत्पादन की क्षमता का परिचय दिया है। अब यही धरती सूर्य की अपार ऊर्जा से प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रही है। खेतों में फसलों के साथ ऊर्जा की नई फसल उगाने की यह पहल किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि अक्षय ऊर्जा की इन संभावनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग और विशेष रूप से किसान परिवारों तक पहुंचे तथा विकसित एवं ऊर्जा आत्मनिर्भर राजस्थान के लक्ष्य को साकार किया जा सके।

-नंदिनी भार्गव, इंटर्न -
मोहन लाल, एपीआरओ,
डीआईपीआर

ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की ओर बढ़ता भारत



डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने वैश्विक राजनीति को नई दिशा दी है। अब भारत केवल अंतरराष्ट्रीय निर्णयों का सहभागी नहीं, बल्कि विकासशील देशों की आकांक्षाओं को वैश्विक विमर्श के केंद्र में लाने वाली एक प्रभावशाली शक्ति बनकर उभर रहा है।

इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक वैश्विक राजनीति में व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्थापित अंतरराष्ट्रीय शक्ति-संतुलन नई चुनौतियों से गुजर रहा है। पश्चिमी देशों के परंपरागत प्रभुत्व के समानांतर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश विश्व व्यवस्था में अपनी न्यायसंगत भागीदारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक संक्रमण के दौर में भारत एक नई भूमिका के साथ सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया है, बल्कि उन देशों की आवाज़ बनने का प्रयास भी किया है, जो लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में अपेक्षित प्रतिनिधित्व से वंचित रहे हैं।

आज प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सकता है या नहीं। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भारत विश्व राजनीति को एक ऐसी नई दिशा दे सकता है, जिसमें आर्थिक सामर्थ्य के साथ मानवीय संवेदनशीलता, राष्ट्रीय हितों के साथ वैश्विक उत्तरदायित्व और प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग को समान महत्व मिले?

भारत की सभ्यतागत चेतना में इस प्रश्न का उत्तर निहित है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' भारत के लिए केवल एक सांस्कृतिक उद्घोष नहीं, बल्कि उसकी विदेश नीति का व्यापक दार्शनिक आधार है। विश्व को एक परिवार मानने की यह दृष्टि आज उस समय अधिक प्रासंगिक हो जाती है, जब दुनिया युद्ध, आर्थिक असमानता, जलवायु संकट और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से जूझ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की विशेषता यह रही है कि भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों का विस्तार किया है। अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और पश्चिम एशिया के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के बावजूद भारत ने अपनी विदेश नीति को किसी एक शक्ति केंद्र के अधीन नहीं होने दिया। यह स्वतंत्र दृष्टिकोण ग्लोबल साउथ के देशों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वे भी अपनी विकास संबंधी प्राथमिकताओं को वैश्विक शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से स्वतंत्र रखना चाहते हैं।

वर्ष 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता इस बदलती भूमिका का ऐतिहासिक उदाहरण बनी। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत की पहल ने वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अफ्रीका की भागीदारी को संस्थागत आधार प्रदान किया। यह उपलब्धि केवल भारतीय कूटनीति की सफलता नहीं थी, बल्कि विकासशील विश्व के प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था।

इसी क्रम में भारत द्वारा आयोजित 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलनों ने विकासशील देशों को अपनी प्राथमिकताओं, समस्याओं और अपेक्षाओं को साझा करने का मंच उपलब्ध कराया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व को केवल कूटनीतिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, बल्कि साझा विकास की जिम्मेदारी के रूप में देखता है। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति भी इस भूमिका को आधार प्रदान करती है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत का बढ़ता महत्व, डिजिटल तकनीक में नवाचार, आधारभूत ढांचे का विस्तार और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां विकासशील देशों के लिए उपयोगी अनुभव प्रस्तुत करती हैं।

विशेष रूप से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय क्षमताएं विकसित की हैं। इसी प्रकार सस्ती दवाओं, टीका निर्माण, कृषि अनुसंधान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की उपलब्धियां ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं उत्पन्न करती हैं। कोरोना महामारी के दौरान 'वैक्सीन मैत्री' पहल के माध्यम से भारत ने अनेक देशों को टीके उपलब्ध कराए। यह उस भारतीय दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति थी, जिसमें वैश्विक संकट के समय सहयोग को केवल आर्थिक लाभ की कसौटी पर नहीं आंका जाता। जलवायु परिवर्तन के प्रश्न पर भी भारत ने विकासशील देशों के हितों को प्रमुखता से उठाया है।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और मिशन लाइफ जैसी पहलें इस बात का संकेत हैं कि भारत पर्यावरण संरक्षण को केवल प्रतिबंधों और दायित्वों के रूप में नहीं, बल्कि तकनीकी नवाचार, जनभागीदारी और सतत विकास के अवसर के रूप में देखता है। भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, हरित वित्त और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की भूमिका ग्लोबल साउथ के लिए विशेष महत्व रखेगी। हालांकि भारत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चीन ने बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अ